

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) संभागीय खाद्य नियंत्रक
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
(4) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 12 सितम्बर, 2008.

विषय:-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए०पी०एल० योजना में माह सितम्बर 2008 हेतु गेहूँ का तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1-7/2008-बीपी-III दिनांक 01 सितम्बर, 2008 द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की ए०पी०एल० योजना में माह सितम्बर 2008 के लिये 8000 मी० टन गेहूँ का एकमुश्त तदर्थ/अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को एकमुश्त आवंटित गेहूँ की मात्रा को जनपदवार ए०पी०एल० राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर संलग्नक के अनुसार आवंटित किया जा रहा है। आप कृपया तदनुसार जनपदों को गेहूँ का वितरण समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. उक्त खाद्यान्न की उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के पत्र दिनांक 01, सितम्बर 2008 से 50 दिन की अवधि की है, अतएव कृपया निर्धारित अवधि के भीतर आवंटित खाद्यान्न का उठान/वितरण सुनिश्चित किया जाये।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि आवंटित एपीएल गेहूँ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित प्रक्रिया के मानकों/नियमों के अन्तर्गत वितरण किया जाय, तथा पूर्ण सतर्कता बरती जाय कि आवंटित खाद्यान्न का लीकेज/डाईवर्जन कदापि न हो। भारत सरकार के आदेश संख्या-4-7/2005 PY IV/PD-I(Pt) दिनांक 17 जनवरी, 2008 का अनुपालन करते हुए उक्त ए०पी०एल० गेहूँ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से वास्तविक राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाय, जिसमें संबंधित अधिकारी का पूर्ण दायित्व रहेगा।

—

.....2

5. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।
6. आवंटित ए0पी0एल0 गेहूँ का भौतिक सत्यापन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराया जाये।

भवदीय,
/
(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या 392-(1)/08-XIX-2/111 खाद्य/2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. अगर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1-7/2008-बीपी-III दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।
6. अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ
7. निजी सचिव, खाद्य मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एन0एस0 नयाल)
अनु सचिव।

वर्ष 2008 में माह सितम्बर 2008 हेतु ए०पी०एल० गेहूँ का
तदर्थ/अतिरिक्त जनपदवार आवंटन
शारानादेश सं० 392/08-XIX-2/111-खाद्य/02 टी०सी, दिनांक सितम्बर, 2008 का संलग्नक
ए०पी०एल० योजना

गढ़वाल संभाग		(मी०टन में)
क०स०	जनपद का नाम	गेहूँ का आवंटन
1.	देहरादून	1480.00
2.	हरिद्वार	1200.00
3.	पौड़ी गढ़वाल	750.00
4.	टिहरी गढ़वाल	480.00
5.	चमोली	290.00
6.	रूद्रप्रयाग	200.00
7.	उत्तरकाशी	210.00
	योग:-	4610.00
कुमायूँ संभाग		
8.	नैनीताल	880.00
9.	बागेश्वर	190.00
10.	पिथौरागढ़	365.00
11.	चम्पावत	180.00
12.	ऊधमसिंह नगर	1230.00
13.	अल्मोड़ा	545.00
	योग:-	3390.00
	महायोग:-	8000.00

(एच०एस०नयाल)
अनुसचिव।